

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1436 का उत्तर

भिंड और दतिया जिलों में आरओबी/आरयूबी

1436. श्रीमती संध्या रायः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश में विशेष रूप से भिंड और दतिया जिलों में ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों की स्थिति सहित उनका ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त जिलों में ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए कितनी निधियाँ स्वीकृत की गई हैं;
- (ग) उक्त जिलों में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज का निर्माण कर रही कंपनी का नाम क्या है; और
- (ङ) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए तय की गई समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

भिंड और दतिया जिलों में आरओबी/आरयूबी के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्रीमती संध्या राय के अतारांकित प्रश्न सं. 1436 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के कार्यों को मंजूरी देना भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा पर इसके प्रभाव, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर शुरू किए जाते हैं।

वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या में
2004-14	4148
2014-24	11945 (लगभग तीन गुना)

वर्ष 2014-24 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कुल 1062 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचली सड़क पुल का निर्माण किया गया जिनमें क्रमशः दतिया में 01 अदद ऊपरी सड़क पुल और 03 अदद निचले सड़क पुल तथा भिंड जिले में 04 ऊपरी सड़क पुल शामिल हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में 6200 करोड़ रुपए की लागत पर 306 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें दतिया जिले में 57.48 करोड़ रु. की लागत से 04 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्य और भिंड जिले में 177.53 करोड़ रु. की लागत पर 04 अदद ऊपरी सड़क पुल कार्य शामिल हैं। दतिया और भिंड जिले में सभी ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्य रेलवे द्वारा अपनी लागत पर निष्पादित किए जा रहे हैं।

किसी भी ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्य का पूरा होना समपार फाटक को बंद करने की सहमति के लिए राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच संरेखण को निश्चित करना, सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) की मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण को हटाना, अतिलंघनकारी जनसुविधाओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशिष्ट परियोजना/कार्य स्थलों के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से भिंड और दतिया सहित 80 स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन

योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
मध्य प्रदेश	80	अकोदिया, अमला, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बानापुरा, बरगवां, ब्योहारी, बेरछा, बेतूल, भिंड, ओपाल, बिजुरी, बीना, बियावरा राजगढ़, छिंदवाड़ा, डबरा, दामोह, दतिया, देवास, गाडरवारा, गंजबासौदा, घोड़ाड़ोंगरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, हरपालपुर, होशंगाबाद, इंदौर, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, जुन्नारदेव, करेली, कटनी जंक्शन, कटनी मुरवारा, कटनी साउथ, खाचरोड, खजुराहो, खंडवा, खिरकिया, लक्ष्मीबाई नगर, मैहर, मकसी, मंडलाफोर्ट, मंदसौर, एमसीएस छतरपुर, मेघनगर, मुरैना, मुलताई, नागदा, नैनपुर, नरसिंहपुर, नीमच, नेपानगर, ओरछा, पांढुरा, पिपरिया, रतलाम, रीवा, रुठियाई, सांची, संत हिरदाराम नगर, सतना, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शामगढ़, श्योपुर कलां, शिवपुरी, श्रीधाम, शुजालपुर, सिहोरा रोड, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, विक्रमगढ़ आलोट

भिंड और दतिया स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं और मौजूदा स्टेशन भवन में सुधार, द्वितीय प्रवेश द्वार का विकास, जल निकासी में सुधार, 12 मीटर

पैदल पार पुल का निर्माण, प्लेटफार्म सतह का निर्माण, लिफ्टों की संस्थापना, नए और बेहतर प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक आदि का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों का आवंटन का विवरण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। मध्य प्रदेश राज्य सात क्षेत्रों अर्थात् मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा कवर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन क्षेत्रों के लिए आवंटन 6339 करोड़ रुपये हैं।
